केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

जलांश

खंड 5 अंक 6 जनवरी 2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

विषयसूची

- बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत समीक्षा गतिविधियों के लिए बैठक
- "बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन के लिए समिति की 9वीं बैठक
- "बांधों के यंत्रीकरण पर तकनीकी मैनुअल" का प्रकाशन/ विमोचन
- जल विद्युत ऊर्जा गृह संरचनाओं पर जल संसाधन विभाग-15 की बैठक
- यूएचएल चरण-III जल विद्युत परियोजना(100 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश के संबंध में के.ज.आ.और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड अधिकारियों की बैठक
- ड्रिप चरण II और एनडीएसए से संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए बैठक
- फरक्का बैराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति की 118वीं बैठक
- के.ज.आ.अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं/ स्थलों का दौरा/निरीक्षण
- दमनगंगा (एकदरे)-गोदावरी घाटी लिंक परियोजना (डीईजी)
- तमिलनाडु जल संसाधन विभाग के सथानुर बांध का तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण दौरा
- ड्रिप(डीआरआईपी) चरण II के तहत यूजेवीएनएल के बांधों की निगरानी और क्यूसी दौरा
- उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित पंचनद बैराज स्थल का दौरा
- धरोई बांध, गुजरात
- ऊपरी सियांग बहुउद्देश्यीय भंडारण परियोजना के कार्यदल की दूसरी बैठक
- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की बैठक
- 25वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और आईसीआईडी की 74वीं आईईसी से संबंधित तौर-तरीकों और मुद्दों पर चर्चा
- विशेष परियोजनाओं और अन्य मुद्दों के संबंध में के.ज.आ द्वारा की गई गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक
- पोलावरम सिंचाई परियोजना के संबंध में वार्ता बैठक
- द्वितीय रावी-ब्यास लिंक परियोजना के पीएफआर पर चर्चा करने के लिए स्थल दौरा
- जल बँटवारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
- भारत-नेपाल पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (पीएमपी) पर चर्चा करने के लिएबैठक
- एनएचपी के लिए परियोजना कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) की दूसरी बैठक
- देश में बाढ़ की स्थिति - दिसंबर 2022
- जलाशय निगरानी
- डेटा कॉर्नर
- इतिहास- सिंचाईऔर विद्युत के लिए चंबल कास्केड

श्री कुशविंदर वोहरा
अध्यक्ष, के ज आ

संदेश

माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा दिनांक 15.12.2022 को भारत जलप्रभाव शिखर सम्मेलन (आईडब्ल्यूआईएस) के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। इसका विषय था'विशाल बेसिन में छोटी नदियों का पुनर्स्थापन और संरक्षण' जिसमें '5पी – पीपल(लोग), पॉलिसी(नीति), प्लान(योजना), प्रोग्राम(कार्यक्रम) और प्रोजेक्ट(परियोजना) के चुनिंदा पहलुओं- मांचित्रण एवं अभिसरण पर बल दिया गया। तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन (15 से 17 दिसंबर 2022) में देश और विदेशों के विशेषज्ञ उन तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनसे बड़ी नदी घाटियों में छोटी नदियों को बचाया जा सके।

के.ज.आ. के अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं/ स्थलों का दौरा किया है। दिसंबर, 2022 में के.ज.आ.के अधिकारियों द्वारा दमनगंगा-गोदावरी घाटी लिंक परियोजना (डीईजी), महाराष्ट्र; प्रस्तावित पंचनदबैराज साइट, उत्तरप्रदेश; धरोई बांध, गुजरात; सथानुर बांध, तमिलनाडु और ड्रिप (डीआरआईपी)-II के अंतर्गत उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) के बांधों का दौरा किया गया।

माननीय जल शक्ति मंत्री ने पोलावरम सिंचाई परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.09.2022 के संदर्भ में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग और के.ज.आ. के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होने के.ज.आ. को छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना राज्यों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी नोटों पर समेकित उत्तर जल्द से जल्द प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

फरवरी, 1996 में भारत और नेपाल के बीच शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना सहित महाकाली नदी के एकीकृत विकास से संबंधित एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए 23.09.2022 को जल संसाधन पर भारत-नेपाल संयुक्त समिति की 9वीं बैठक आयोजित की गई। सचिव (जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने 23.12.2022 को एक बैठक की अध्यक्षता की,जिसमें विदेश मंत्रालय,जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, के.ज.आ.,केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम और वैपकोस के अधिकारियों ने भाग लिया।

मैं सभी को नववर्ष-2023 की शुभकामनाएँ देता हूं और एक सुखद, समृद्ध और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ।

वोहरा

डी एंड आर विंग के तहत गतिविधियाँ

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत समीक्षा गतिविधियों के लिए बैठक

माननीय मंत्री (जल शक्ति) की अध्यक्षता में 09.12.2022 को श्रम शक्ति भवन में बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के साथ-साथ बाहरी रूप से वित्त पोषित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण-II से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में श्री चंद्रशेखर अय्यर, अध्यक्ष, के.ज.आ., श्री नवीन कुमार,सदस्य (डीएंडआर), के.ज.आ., के.ज.आ. के अन्य अधिकारी और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एनसीडीएस के दो विशेषज्ञ सदस्य उपस्थित थे।

"बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन के लिए समिति की 9वीं बैठक"

"बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन" के लिए समिति की 9वीं बैठक 15 दिसंबर 2022 को श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। यह बैठक अंतिम रिपोर्ट को स्वीकृत किए जाने हेतु उस पर चर्चा और विचार करने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में, समिति ने अंतिम रिपोर्ट में अतिरिक्त जानकारी और टिप्पणियों के बिंदु-वार प्रतिक्रियाओं के सारांश को शामिल करने की शर्त के साथ अंतिम रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया।

"बांधों के यंत्रीकरण पर तकनीकी मैनुअल" का प्रकाशन/ विमोचन

श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग द्वारा श्री नवीन कुमार, सदस्य (डीएंडआर), के.ज.आ. और के.ज.आ.के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 30/12/2022 को "बांधों के यंत्रीकरण पर तकनीकी मैनुअल" को प्रकाशित किया गया था।"

इस मैनुअल को यंत्रीकरण निदेशालय, बांध सुरक्षा संगठन, के.ज.आ. द्वारा तैयार किया गया है।

यह मैनुअल बांध यंत्रीकरण से संबंधित कई उपलब्ध भारतीय मानक कोड में निहित बांध यंत्रीकरण के प्रावधानों का संकलन है और के.ज.आ.के बड़े बांध के यंत्रीकरण हेतु दिशानिर्देशों तथा जल-मौसम वैज्ञानिक, भू-विश्लेषणात्मक,भू-तकनीकी और भू-कंपीय उपकरणों के तकनीकी विनिर्देशों पर आधारित है।

मैनुअल का उद्देश्य बांध मालिकों और अभ्यासरत अभियंताओं को बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यंत्रीकरण के माध्यम से बांधों की निगरानी, मूल्यांकन और दीर्घकालिक स्वास्थ्य मूल्यांकन में मदद करना है।

जल विद्युत ऊर्जा गृह संरचनाओं पर जल संसाधन विभाग-15 की बैठक

श्री एस.के. "सिबल, मुख्य अभियंता, डिजाइन (एनएंडडब्ल्यू) इकाई ने 07.12.2022 को मानक भवन, बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली में जल संसाधन विभाग-15 के अध्यक्ष के रूप में "जल विद्युत ऊर्जा गृह संरचनाओं" पर जल संसाधन विभाग-15 की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की।"

निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिए गए हैं:

क. आईएस 12837:1989 और आईएस 5496:1993 को अंतिम रूप दिया गया।

ख. समिति ने मार्च 2023 में पुन: पुष्टि के लिए लंबित सभी मानकों की पुष्टि व संशोधन तथा 14 भारतीय मानकों की समीक्षा करने का निर्णय लिया।

ग. के.ज.आ. ने भूमिगत जल-विद्युत ऊर्जा स्टेशनों में "योजना,अभिन्यास और कोटर डिजाइन" के लिए दिशानिर्देश के मसौदे पर इनपुट दिए। [आईएस 9120 का प्रथम संशोधन"जल संसाधन विभाग 15 (डब्ल्यूडी 2)"]

उपरोक्त मसौदे पर के.ज.आ. के दिए गए इनपुट पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया।

एसजेवीएनएल और वोइथहाइड्रो लिमिटेड ने आईएस 12800 (भाग 1):1993 प्रथम संशोधन और आईएस 7418:1991 [प्रथम संशोधन] पर अपने इनपुट दिए। समिति ने पैनल से एसजेवीएनएल और वोइथ हाइड्रो लिमिटेड के इनपुट पर विचार करने का अनुरोध किया।

यूएचएल चरण-III जल विद्युत परियोजना(100 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश के संबंध में के.ज.आ.और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड अधिकारियों की बैठक

यूएचएल-III जल विद्युत परियोजना, (100 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश का पेनस्टॉक 17 मई 2020 को 50% क्षमता पर चल रही पहली इकाई के परीक्षण के दौरान टूट गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा यूएचएल-III जल विद्युत परियोजना के पेनस्टॉक की बहाली और सुधार के संबंध में के.ज.आ. से सलाह देने का अनुरोध किया गया था। के.ज.आ. ने इस मुद्दे की जांच की है और एफईएम अध्ययन किया है। पेनस्टॉक के पुनरुद्धार/की बहाली पर के.ज.आ. ने अध्ययन रिपोर्ट के साथ सलाह सितंबर 2022 में पहले ही दे दी है।

अब, एचपीएसईबी लिमिटेड ने डिजाइन/परिचालन मापदंडों के विभिन्न संयोजनों के लिए मौजूदा पहुंच के कार्यों को जोड़ने/मजबूत करने के संबंध में के.ज.आ.की और सलाह मांगी। इस संबंध में, निदेशक, एचपीएसईबी लिमिटेड ने के.ज.आ. से एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया। तदनुसार, 23.12.2023 को के.ज.आ. और एचपीएसईबी लिमिटेड के अधिकारियों की एक बैठक के.ज.आ. में आयोजित की गई। पेनस्टॉक पहुंच जिन्हें बदलने का प्रस्ताव नहीं है, के संबंध में एचपीएसईबी लिमिटेड की चिंताओं पर, बैठक के दौरान स्वतंत्र रूप से चर्चा की गई है।

ड्रिप चरण II और एनडीएसए से संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए बैठक

18 नवंबर,2022 की बैठक में लिए गए निर्णयों जिसमें ड्रिप योजना और एनडीएसए से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी, की समीक्षा के लिए सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में 19.12.2022 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। श्री नवीन कुमार, सदस्य(डी एंड आर),के.ज.आ., के.ज.आ. के अन्य अधिकारियों के साथ-साथ मंत्रालय और विश्व बैंक के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

फरक्का बैराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति की 118वीं बैठक

श्री नवीन कुमार, सदस्य (डीएंडआर), केंद्रीय जल आयोग और अध्यक्ष (टीएसी-एफबीपी) की अध्यक्षता में 21.12.2022 को फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) की तकनीकी सलाहकार समिति की 118वीं बैठक आयोजित की गई थी।

केंद्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) पटना, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) पुणे, श्यामाप्रसाद मुकर्जी पोर्ट कोलकाता ,हाइड्रोलिक्स विभाग, जल संसाधन विभाग ,बिहार सरकार, सिंचाई और जलमार्ग निदेशालय पश्चिम बंगाल के अधिकारी और विशेष आमंत्रित अधिकारी आयुक्त (एफएम), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, मुख्य अभियंता, डिजाइन (ई एंड एनई) के.ज.आ, मुख्य अभियंता, डिजाइन (एनएंडडब्ल्यू) के.ज.आ, निदेशक केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन (सीएसएमआरएस) ने प्रत्यक्ष रूप से बैठक में भाग लिया।

बैठक में, किनारों की सुरक्षा और फरक्का बैराज की सुरक्षा के लिए क्षरण रोधी उपायों से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

तकनीकी सलाहकार समिति- फरक्का बैराज परियोजना (टीएसी-एफबीपी) की बैठक की सिफारिश निम्नलिखित थी: -

1. यह सिफारिश की गई थी कि फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) 1140 मीटर से 3200 मीटर तक श्रृंखला-माप के लिए क्षरण रोधी उपायों को के.ज.आ. द्वारा जारी ड्राइंग के अनुसार निष्पादित कर सकता है।

2. यह सिफारिश की गई थी कि फरक्का बैराज तालाब में प्रतिप्रवाह शोलों के आसपास नदी के तट कटाव पैटर्न पर तट रेखा के संशोधन के प्रभाव का आकलन करने के लिए एफबीपी मॉडल अध्ययन करने हेतु केंद्रीय केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला (सीडब्ल्यूपीआरएस) को कह सकता है।

फरक्का बैराज के डाउनस्ट्रीम में Ch.1350.00m से 1450.00m और Ch.4500.00m से 4700.00m Ch.4800.00 से 4960.00 मी के लिए कटावरोधी कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

के.ज.आ.अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं/स्थलों का दौरा/निरीक्षण

दमनगंगा (एकदरे)-गोदावरी घाटी लिंक परियोजना (डीईजी)

डिजाइन (एनडब्ल्यूएंडएस) इकाई के अंतर्गत सीएमडीडी (एनडब्ल्यूएंडएस) को दमण गंगा (वाल/वाघ)-वैतरना-गोदावरी (कडवा-देव) लिंक (डीवीजी) और दमनगंगा (एकदरे)- गोदावरी लिंक परियोजनाएं, महाराष्ट्र के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। इन परियोजनाओं में आरसीसी बांध और इसकी सहायक संरचनाओं के पूर्ण डिजाइन व ड्राइंग की तैयारी करना और डिजाइन अध्यायों लिखना शामिल है। डीवीजी लिंक परियोजना से दमनगंगा और वैतरणा नदी घाटियों के अधिशेष जल को दिल्ली-मुंबई औद्योगिक क्षेत्र की घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति की जरूरतों को पूरा करने तथा नासिक जिले के सूखा संभावित सिंनार तालुका में सिंचाई हेतु स्थानांतरित करना है। डीवीजी लिंक में, चार प्रस्तावित आर.सी.सी बांध हैं:

1) वैल नदी पर नीलमती, 2) दमनगंगा की सहायक नदी वाघ नदी पर मेत, 3) पिंजल नदी पर कोशिमशेत और 4) वैतरणा बेसिन में गर्गई नदी पर उधले।

चार बांधों में से, मेत आरसीसी बांध का डिजाइन अध्याय और इसका प्रासंगिक चित्र तैयार कर लिया गया है और दिनांक 16.08.2022 को इसे एनडब्ल्यूडीए को जारी कर दिया गया है। शेष तीन बांध अग्रिम चरण में हैं।

प्रस्तावित दमनगंगा (एकदरे)-गोदावरी घाटी लिंक परियोजना (डीईजी) में दमनगंगा बेसिन के अधिशेष जल को प्रस्तावित एकदरे बांध स्थल से गोदावरी घाटी में मौजूदा गंगापुर जलाशय तक भेजना है। इसे दो चरणों में लिफ्ट द्वारा और फिर गुरुत्वाकर्षण प्रवाह द्वारा सुरंग के माध्यम से मोड़ने की परिकल्पना की गई है।

यह परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में एकदरे गांव के पास स्थित है। एकदरे आरसीसी बांध का डिजाइन अध्याय और इसका प्रासंगिक चित्र तैयार कर लिया गया है और दिनांक 28.11.2022 को इसे एनडब्ल्यूडीए को जारी कर दिया गया है

श्री दर्पण तलवार, निदेशक, एचसीडी (एनडब्ल्यू एंड एस) निदेशालय, के.ज.आ.और श्री कयूम मोहम्मद, निदेशक, सीएमडीडी (एनडब्ल्यू एंड एस) निदेशालय, के.ज.आ.ने जीएसआई अधिकारियों के साथ 20-23 दिसंबर, 2022 तक परियोजना स्थल का दौरा किया।

टीम ने बांध के महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा किया अर्थात बांध एक्सिस, ईडीए और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं।

टीम ने पाया कि चयनित साइट आरसीसी बांध बनाने के लिए उपयुक्त है और सभी साइट कर्तन क्षेत्रों, कमजोर क्षेत्रों और दोषों से मुक्त हैं।

तमिलनाडु जल संसाधन विभाग के सथानुर बांध का तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण दौरा

श्री समीर कुमार शुक्ला, निदेशक, एफई एंड एसए निदेशालय ने 05-07 दिसंबर, 2022 के दौरान निदेशक केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन और के.ज.आ अधिकारियों द्वारा बाहरी रूप से वित्त पोषित ड्रिप (डीआरआईपी) चरण-II योजना के तहत सथानुर बांध, तमिलनाडु जल संसाधन विभाग के तीसरे पक्ष के गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण दौरे में सीपीएमयू-ड्रिप(डीआरआईपी) की ओर से भाग लिया।

ड्रिप(डीआरआईपी) चरण II के तहत यूजेवीएनएल के बांधों की निगरानी और क्यूसी दौरा

के.ज.आ और केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन (सीएसएमआरएस) अधिकारियों की संयुक्त टीम ने 15-17 दिसंबर, 2022 के दौरान यूजेवीएनएल के जोशियारा और मनेरी का निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण दौरा किया। अधिकारियों ने इन बांधों पर चल रहे विभिन्न पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण किया और प्रगति की समीक्षा की।

जोशियारा बैराज पर चल रहे कट-ऑफ ड्रेन निर्माण एवं ग्राउटिंग कार्य का निरीक्षण

उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित पंचनद बैराज स्थल का दौरा

श्री एन.एन. राय, निदेशक, हैदराबाद (एस) निदेशालय और श्री अक्षत जैन, उपनिदेशक, हैदराबाद (डीएसआर) निदेशालय ने प्रस्तावित पंचनद बैराज परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के जल विज्ञान अध्याय की तैयारी के लिए परामर्श कार्य के संबंध में 19 दिसंबर 2022 से 21 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित पंचनद बैराज स्थल का दौरा किया। पंचनद बैराज उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में यमुना नदी पर प्रस्तावित है। यह पांच नदियों जैसे कि यमुना चंबल, सिंध, पहुज और क्वारी के संगम के अनुप्रवाह में है ।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य यमुना नदी के दाहिने तट पर स्थित उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में लगभग 40550 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता पैदा करना है

सिंचाई परियोजना बनाने के अलावा बैराज पीने और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी उपलब्ध कराएगा।

धरोई बांध, गुजरात

श्री एस.एस. बख्शी, निदेशक, डीएसएम, के.ज.आ ने सीएसएमआरएस टीम और निदेशक (एमओएन), के.ज.आ, गांधीनगर के साथ डीआरआईपी-II के तहत चल रहे कार्यों की गुणवत्ता निरीक्षण और निगरानी के लिए 15-17 दिसंबर 2022 तक धरोई बांध, गुजरात का दौरा किया।

ऊपरी सियांग बहुउद्देश्यीय भंडारण परियोजना के कार्यदल की दूसरी बैठक

श्री विवेक त्रिपाठी, मुख्य अभियंता, डिजाइन (ईएंडएनई), केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) की अध्यक्षता में 14.12.2022 को ऊपरी सियांग बहुउद्देश्यीय भंडारण परियोजना (यूएसएमएसपी) के कार्यदल की दूसरी बैठक आयोजित की गई थी।

केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएसएमआरएस) और राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम (एनएचपीसी) के अधिकारियों ने भौतिक रूप से बैठक में भाग लिया, जबकि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के अधिकारियों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से बैठक में भाग लिया। बैठक में यूएसएमएसपी की व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार करने की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। तकनीकी मुद्दों पर चर्चा करने और चल रहे भू-भौतिक जांच की प्रगति की निगरानी करने हेतु के.ज.आ. के अधिकारियों के साथ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम (एनएचपीसी) के अधिकारियों के दौरे का सुझाव दिया गया था। राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम (एनएचपीसी) द्वारा साइट पर प्रस्तावित ड्रिलिंग कार्य किए जाने हैं। इस संबंध में, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम (एनएचपीसी) से ड्रिलिंग से पूर्व के कार्य पूरे करने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा एनएचपीसी द्वारा प्रस्तावित सभी बांध स्थल/एक्सिस के फायदे और नुकसान पर चर्चा की गई।

बांधों के निरीक्षण की स्थिति पर साप्ताहिक रिपोर्ट

राज्यवार किए गए बांध निरीक्षण की स्थिति और बांध सुरक्षा एवं राज्य बांध सुरक्षा संगठन पर राज्य समिति के गठन/स्थापना पर साप्ताहिक रिपोर्ट जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय को सौंपी जा रही है। 19.01.2023 की स्थिति के अनुसार, राज्यों द्वारा यह बताया गया है कि वर्ष 2022 में लगभग 3919 बांधों के लिए मानसून-पूर्व निरीक्षण किए गए हैं और अब तक लगभग 3592 बांधों के लिए मानसून-पश्चात निरीक्षण किए गए हैं। बांध सुरक्षा अधिनियम (डीएसए), 2021 के प्रावधानों के अनुसार, सभी 31 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों ने बांध सुरक्षा पर राज्य समिति (एससीडीएस) का गठन किया है और राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) की स्थापना की है।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की बैठक

श्री नवीन कुमार, अध्यक्ष, एनडीएसए और सदस्य (डीएंडआर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में सात राज्यों (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक) के एसडीएसओ के साथ राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की एक बैठक 27.12.2022 को आयोजित की गई थी, जिसमें अधिकतम संख्या में निर्दिष्ट बांध (प्रत्येक राज्य में 200 से अधिक) और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शामिल थे। सदस्य (तकनीकी), सदस्य (नीति और अनुसंधान), सदस्य (विनियम) और सदस्य (आपदा और अनुकलन/लचीलापन) के प्रतिनिधि ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक बांध सुरक्षा अधिनियम (डीएसए), 2021 के तहत विभिन्न मुद्दों को

संबोधित करने के लिए आयोजित की गई थी।
सदस्यों द्वारा निम्नलिखित कार्यसूची पर चर्चा की गई:
1.निर्दिष्ट बांधों की सूची को अद्यतन करना
2.एनडीएसए के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति
3.मानसून पश्चात निरीक्षण की स्थिति
प्रमुख बांध संबंधी घटनाओं और विफलताओं का रिकॉर्ड बनाए रखना

जल आयोजन एवं परियोजना स्कन्ध के तहत गतिविधियां

25वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और आईसीआईडी की 74वीं आईईसी से संबंधित तौर-तरीकों और मुद्दों पर चर्चा

13.12.2022 को, श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव ने 25वीं कांग्रेस के आयोजन पर विभिन्न मुद्दों पर होने वाली चर्चा की अध्यक्षता की-जैसे वित्तीय तौर-तरीके, आयोजन का प्रारंभिक अनुमान, आयोजन के लिए बैंक खाता, आयोजन के सुचारु आयोजन के लिए समितियां, आयोजन स्थल की बुकिंग और सांस्कृतिक/तकनीकी पर्यटन, मजबूत परिवहन तंत्र, इवेंट प्रबंधन आदि।

भारत ने वर्ष 1951 और 1966 में क्रमशः आईसीआईडी की पहली और छठी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी की और के.ज.आ में स्थित भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी समिति (आईएनसीआईडी), भारत आगामी 25वीं कांग्रेस की मेजबानी कर रही है, जो 57 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत में प्रतिष्ठित आईसीआईडी कांग्रेस की वापसी का प्रतीक है, और जो इसे भारत के लिए गौरव का क्षण बनाता है। 25वीं आईसीआईडी कांग्रेस 1 से 8 नवंबर, 2023 तक विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाली है। विशाखापत्तनम में आयोजित इस कार्यशाला में दुनिया भर के 1000+ प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है।आयोजन के बड़े पैमाने और आकार को देखते हुए बारीक से बारीक विवरणों को ध्यान में रखते हुए मजबूत योजना की आवश्यकता है। भारत में आईसीआईडी कार्यक्रमों के समग्र समन्वय के लिए अप्रैल, 2022 में श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति का गठन किया गया था। आयोजन समिति में के.ज.आ, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, आईसीआईडीऔर आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, गुंटूर (एपी)के सदस्य हैं। चूँकि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार इस आयोजन की सह-आयोजक और प्रायोजक है, श्री शशि भूषण कुमार, प्रधान सचिव (जल संसाधनविभाग), आंध्र प्रदेश सरकार आयोजन समिति में एपी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।

25वीं आईसीआईडी कांग्रेस के लिए एक समर्पित वेबसाइट जून 2022 में शुरू की गई थी और आईसीआईडी द्वारा कांग्रेस के लिए विषयगत प्रश्नों को भी अंतिम रूप दिया गया है। आईसीआईडी कांग्रेस के लिए कागजात की मांग की भी घोषणा की गई थी।

इसके अलावा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) ने टिप्पणी की कि सभी संबंधित पक्षों को अपेक्षित प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि इस कार्यक्रम को अच्छे आतिथ्य और सुविधाओं के साथ एक महान तकनीकी कार्यक्रम के रूप में याद किया जा सके। यह एनसीआईडी और भारत सरकार के साथ-साथ आंध्र प्रदेश सरकार को भी गौरवान्वित करेगा।

विशेष परियोजनाओं और अन्य मुद्दों के संबंध में सीडब्ल्यूसी द्वारा की गई गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक

अन्य संबद्ध मुद्दों के साथ विशेष परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए विशेष सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में 12.12.2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, और के.ज.आ. के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान 2 परियोजनाओं अर्थात शाहपुरकंडी बांध परियोजना और रेणुकाजी बांध परियोजनाओं पर चर्चा की गई। शाहपुरकंडी बांध परियोजना के संबंध में, विशेष सचिव ने सीडब्ल्यूसी को शाहपुरकंडी बांध परियोजना की आरसीई को 15.01.2023 तक हर तरह से अंतिम रूप देने के लिए कहा, ताकि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग स्तर पर इसकी मंजूरी के लिए आगे की कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, रेणुकाजी बांध परियोजना के लिए, विशेष सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने निर्देश दिया कि डिजाइन प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए भूविज्ञान सहित परियोजना में शामिल विभिन्न पहलुओं में तकनीकी दक्षता रखने वाले विशेषज्ञों का एक स्थायी समूह बनाया जा सकता है। इसके अलावा, सीडब्ल्यूसी को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का काम सौंपा गया कि एचपीपीसीएल द्वारा बिना किसी देरी के, अधिमानतः 7 दिनों में समूह का गठन किया जाए। इसके बाद, विशेषज्ञ समूह जनवरी, 2023 तक सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रस्तावित डिजाइन परिवर्तनों पर अपने विचार व्यक्त कर सकता है।

पोलावरम सिंचाई परियोजना के संबंध में वार्ता बैठक

पोलावरम सिंचाई परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के पोलावरम मंडल के रामाययापेटा गांव के पास गोदावरी नदी पर निष्पादित किया जा रहा है। इस बहुउद्देशीय प्रमुख परियोजना में 4.36 लाख हेक्टेयर की अंतिम सिंचाई क्षमता बनाने के लिए एक अर्थ कम रॉकफिल (ईसीआरएफ) बांध के साथ-साथ सैडल मृदाबांध, एक स्पिलवे, सिंचाई सुरंग, नेविगेशन सुरंग और चैनल और दोनों किनारों पर दो मुख्य नहरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में 540 गांवों को 960 मेगावाट जलविद्युत, पेयजल आपूर्ति और 84.7 हजार मिलियन घन फीट (टीएमसी) पानी (नुकसान सहित) का कृष्णा बेसिन में मोड़ने की भी परिकल्पना की गई है।

पोलावरम सिंचाई परियोजना के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 06.09.2022 के आदेश के संदर्भ में माननीय मंत्री (जल शक्ति) के लिए एक वार्ता बैठक 09.12.2022 को आयोजित की गई थी।

बैठक में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और के.ज.आ. के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, माननीय मंत्री (जल शक्ति) ने निर्देश दिया कि के.ज.आ. जल्द से जल्द छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना राज्यों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी नोटों पर समेकित उत्तर प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, इन राज्यों को समेकित उत्तर जारी करने के 10 दिनों के भीतर, के.ज.आ.राज्यों के बीच विचारों के अभिसरण की तलाश के लिए आगे की चर्चा के लिए एक बैठक बुला सकता है।

द्वितीय रावी-ब्यास लिंक परियोजना के पीएफआर पर चर्चा करने के लिए स्थल दौरा

भारत सरकार ने लोगों के लाभ के लिए पहचानी गई राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने की दृष्टि से ग्यारहवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय परियोजनाओं की एक योजना को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परियोजनाओं को केंद्रीय अनुदान के रूप में सिंचाई और पेयजल घटक की लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

द्वितीय रावी- ब्यास लिंक परियोजना व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्ट (पीएफआर) के चरण में है। रावी और ब्यास /सतलुज के बीच लिंक के माध्यम से सीमा पार बहने वाले पानी के दोहन को रोकने के लिए व्यवहार्यता/ संभावनाओं की खोज की जा रही है। दूसरी रवि ब्यास लिंक परियोजना के पीएफआर पर चर्चा करने के लिए सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में के.ज.आ. (मुख्यालय), के.ज.आ. (चंडीगढ़), जल संसाधनविभाग (पंजाब) और संबंधित संगठनों के अधिकारियों के साथ 20.12.2022 से 22.12.2022 तक एक स्थल दौरा किया गया।

स्थल दौरे के दौरान, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. ने प्रस्तावित द्वितीय रवि ब्यास लिंक परियोजना (नेशनल परियोजना) की विभिन्न साइटों का दौरा किया और जल संसाधनविभाग पंजाब और संबंधित संगठनों के अधिकारियों के साथ वार्ता बैठकें कीं।

सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. ने निर्देश दिया कि जल संसाधन विभाग, पंजाब -जल संसाधन विभाग, गोवा की आवश्यकता के अनुसार द्वितीय रावी-ब्यास लिंक परियोजना के लिए प्रस्तावित संरेखण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है और अन्य संबंधित संगठन की आवश्यकता के अनुसार उझ बहूद्देशीय परियोजना के निर्माण के बाद संशोधित जल-

उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध भूमि और भूमि अधिग्रहण आदि जैसे संभावित मुद्दों को उजागर करते हुए 15 दिनों में सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

जल बँटवारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ और भारत सरकार के पदेन अपर सचिव और अध्यक्ष, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की अध्यक्षता में 06.12.2022 को के.ज.आ, नई दिल्ली में ओखला की यमुना अनुप्रवाह में ई-प्रवाह को आगरा तक बनाए रखने के बारे में सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश; सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, एनएमसीजी, के.ज.आ और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी ।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और टीएचडीसीएल के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) और अध्यक्ष, यूवाईआरबी ने 09.11.2022 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश और टीएचडीसीएल द्वारा प्राप्त/प्रस्तुत किए जाने वाले डेटा की स्थिति के बारे में पूछताछ की।

इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के बाद, निम्नलिखित कार्य बिंदु सामने आए:

(i) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार यूवाईआरबी कार्यालय को 1 नवंबर से 31 मई की अवधि के लिए पिछले 10 वर्षों के लिए ऊपरी गंगा नहर में वास्तविक रूप से परिवर्तित प्रवाह के साथ-साथ एमसीएम में दैनिक आधार पर नदी में छोड़े गए प्रवाह के संबंध में डेटा प्रस्तुत करेगा।

ii) केंद्रीय जल आयोग उपरोक्त अवधि के लिए यूवाईआरबी कार्यालय को भीमगोडा बैराज के गंगा नदी के डी/एस का साइट डेटा प्रदान करेगा।

आरएम विंग के अंतर्गत गतिविधियां

भारत-नेपाल पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (पीएमपी) पर चर्चा करने के लिए बैठक

फरवरी 1996 में भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी सहित शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना के एकीकृत विकास से संबंधित एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत, दोनों देश एक एकीकृत परियोजना के रूप में पंचेश्वर बहु-उद्देशीय परियोजना (पीएमपी) को लागू करने के लिए सहमत हो गए हैं। इस परियोजना पर दोनों देशों के बीच मौजूद द्विपक्षीय तंत्र में नियमित रूप से चर्चा की जाती है।

पिछले साल, परियोजना की डीपीआर को शीघ्र अंतिम रूप देने से संबंधित मामले पर काठमांडू, नेपाल में 23.09.2022 को आयोजित भारत-नेपाल जल संसाधन संयुक्त समिति (जेसीडब्ल्यूआर) की 9वीं बैठक में चर्चा की गई थी। उपरोक्त के अलावा, इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए, सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की अध्यक्षता में 23.12.2022 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विदेश मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, के.ज.आ. , केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, एनएचपीसी और वैपकोस के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में, सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) ने जोर देकर कहा कि परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हो रहे गतिरोध को दूर करडीपीआर को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रयास किया जान चाहिए। नवीनतम उपलब्ध डेटा पर विचार करते हुए पंचेश्वर बांध और मध्यवर्ती जलग्रहण क्षेत्र में जल उपलब्धता अध्ययन करने का निर्देश दिया गया। परियोजना के लिए अनुमानित लागत और विद्युत संभाव्यता अध्ययन के संशोधन के लिए भी निर्देश दिए गए थे। अन्य

चर्चाओं के साथ-साथ, भारतीय जलग्रहण क्षेत्र में महाकाली/शारदा की सहायक नदियों पर अतिरिक्त परियोजनाओं (भंडारण/रन-ऑफ) के निर्माण के विकल्प की खोज करने से संबंधित मामले पर भी चर्चा की गई, जिसमें परिकल्पित पीएमपी पर उनका प्रभाव भी शामिल था। इस संबंध में विशेषज्ञों के एक समूह जिसमें मुख्य अभियंता, वाईबीओ, के.ज.आ. , मुख्य अभियंता, सीईए और कार्यकारी निदेशक, डब्ल्यूएपीसीओएस शामिल है को एक रिपोर्ट तैयार करने कार्य सौंपा गया।

उपरोक्त बैठक दिनांक 23.12.2022 में के.ज.आ. से, श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, अध्यक्ष, के.ज.आ, श्री पी एम. स्कॉट, सदस्य (आरएम), के.ज.आ, श्री एस.के सिबल, मुख्य अभियंता, डिजाइन (एनएंडडब्ल्यू), के.ज.आ, श्री जी.के. अग्रवाल, मुख्य अभियंता, यमुना बेसिन संगठन, के.ज.आ और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

एनएचपी के लिए परियोजना कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) की दूसरी बैठक

सदस्य (आरएम), के.ज.आ और परियोजना समन्वयक (एनएचपी) की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) की दूसरी बैठक 06.12.2022 को आयोजित की गई थी। यह बैठक के.ज.आ द्वारा की गई एनएचपी गतिविधियों की समीक्षा करने के साथ-साथ पीआईसी की पिछली बैठक में के.ज.आ. के प्रत्येक संबंधित संगठन द्वारा की गई कार्य योजना के निष्पादन की समीक्षा करने के साथ-साथ मुख्य अभियंता, पी एंड डीओ और नोडल अधिकारी, एनएचपी-के.ज.आ. के तहत बैठक के दौरान और कार्रवाई में तेजी लाने के लिए आयोजित की गई थी

बैठक के दौरान, एनएचपी के तहत कई गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा हुई, जैसे- मध्यम और दीर्घकालिक पूर्वानुमान के लिए यमुना, नर्मदा और कावेरी बेसिनवार ईएचपी मॉडल, तलछट दर और तलछट के आकलन के लिए भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग, सात नदी बेसिन में परिवहन, गंगा बेसिन में जलप्लावन पूर्वानुमान सहित प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली, गंगा बेसिन में एकीकृत जलाशय संचालन, बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी में बाढ़ और गाद के मुद्दे का अध्ययन, अरुणाचल प्रदेश में जलाशय तलछट और बाथीमीट्रिक सर्वेक्षण, आरटीडीएस, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में आरटीडीएस, गैर-संपर्क प्रवाह माप प्रणाली (वेलोसिटी रडार प्रणाली)।

देश में बाढ़ की स्थिति - दिसंबर 2022

ब्रह्मपुत्र, बराक और झेलम घाटियों में 01.05.2022 को नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि शुरू हुई। 1 मई से 31 दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान, 11558 बाढ़ पूर्वानुमान (6779 स्तर और 4779 प्रवाह) जारी किए गए, जिनमें से 10845 (6476 स्तर और 4369 प्रवाह) पूर्वानुमान 93.83% कीप्रतिशत सटीकता कीसीमाकेभीतरथे।केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से दिसंबर 2022 में 01 रेड बुलेटिन (चरम बाढ़ की स्थिति के लिए) और 03 ऑरेंज बुलेटिन (बाढ़ की गंभीर स्थिति के लिए) जारी किए गए।

1.05.2022 से 31.12.2022 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों में चरम बाढ़ की स्थिति:

ग्यारह बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन में चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

क्र. सं	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन	अवधि	
					से	तक
1.	असम	नगांव	कोपिली	कामपुर	15/05/2022 16/06/2022	21/05/2022 22/06/2022
2.	बिहार	किशनगंज	महानंदा	तैयबपुर	29/06/2022	29/06/2022
3.		सुपौल	कोसी	बसुया	02/08/2022	02/08/2022
4.		सिवान	घागरा	दारौली	14/10/2022	16.10.2022
5.	तेलंगाना	भूपालपल्ली	गोदावरी	कालेश्वरम	14/07/2022	15/07/2022
6.		कुमारमभीम	वर्धा	सिरपुर(टी)	14/07/2022	17/07/2022
7.	आंध्र प्रदेश	अल्लूरी सीताराम राजू	साबरी	चिंटुरु	15/07/2022	19/07/2022
8.	राजस्थान	करौली	चंबल	मंडेरियल	25/08/2022	25/08/2022
9.		धौलपुर	चंबल	धौलपुर	25/08/2022	26/08/2022
10.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	राप्ती	बलरामपुर	08/10/2022	13/10/2022
11.		सिद्धार्थनगर	राप्ती	बंसी	14/10/2022	19/10/2022

81 बाढ़ नियंत्रण स्टेशनों ने चरम बाढ़ की स्थिति देखी।

बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों में गंभीर बाढ़ की स्थिति

असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और गुजरात राज्यों में 95 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों ने गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी।

सामान्य बाढ़ की स्थिति से ऊपर

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटक में 46 एफएफ स्टेशनों पर सामान्य बाढ़ की स्थिति से ऊपर की स्थिति देखी गई।

सीमा से अधिक अंतर्वाह वाले जलाशय

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 89 जलाशय को अपनी सीमा से अधिक अंतर्वाह प्राप्त हुआ।

31.12.2022 को योजनाओं की वित्तीय प्रगति।

(राशि करोड़ में और विशिष्टत: कें.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रं.	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान 2022-23	व्यय	व्यय (%में)
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	185.00	119.246	64.46%
2.	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	08.000	6.9544	86.93%
3.	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	23.203	6.9972	30.16%
4.	निर्देशन एवं प्रशासन (डी एंड ए) - प्रमुख कार्य और ओई (एसएपी)	11.15	4.7532	42.63%
5.	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी)	44.37 (RE)	11.994	27.17%
6.	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II	100.00	3.64	3.64%

के.ज.आ. की अन्य गतिविधियां

जलाशय निगरानी

के.ज.आ साप्ताहिक आधार पर देश के 143 जलाशयों की सजीव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 46 जलाशयों में 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ जल विद्युत लाभ है। इन 143 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 177.464 बीसीएम है जो देश में सृजित 257.812 बीसीएम की सजीव भंडारण क्षमता का लगभग 68.83% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 29.12.2022के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 132.232 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 75% प्रतिशत है। हालांकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध कुल सजीव भंडारण 129.725 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों के सजीव भंडारण का औसत 110.841 बीसीएम था।

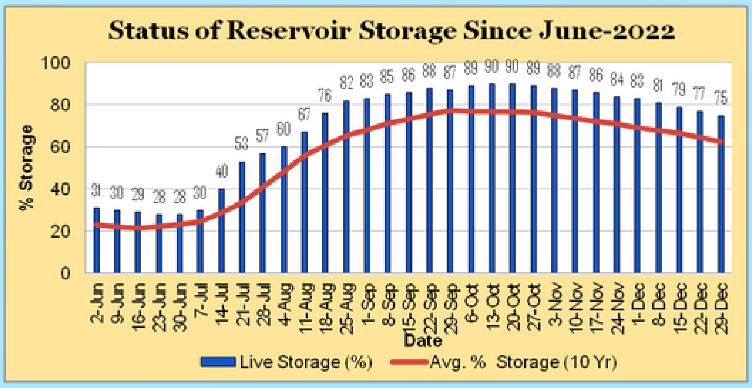

इस प्रकार, दिनांक 29.12.2022 के बुलेटिन के अनुसार 143 जलाशयों में उपलब्ध सजीव भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सजीव भंडारण का 102 प्रतिशत और पिछले दस वर्षों के औसत सजीव भंडारण का 119 प्रतिशत है।

डेटा कॉर्नर- 2001 से 2021) की अवधि के लिए देश की प्रमुख नदियों में औसत दशकीय प्रवाह (अरब घन मीटर में)

क्रम सं.	नदी का नाम	अंतिम डिस्चार्ज निगरानी केंद्र का नाम	राज्य का नाम	दशकीय औसत प्रवाह 2001 से 2011	दशकीय औसत प्रवाह 2011 से 2021
1.	गंगा	फरक्का	पश्चिम बंगाल	315.423	310.062
2.	ब्रह्मपुत्र	पंचरत्न	असम	483.541	470.454
3.	तीस्ता	दोमोहनी	पश्चिम बंगाल	21.318	24.094
4.	कृष्णा	वाडेनपल्ली	आंध्र प्रदेश	18.764	12.993
5.	गोदावरी	पोलावरम	आंध्र प्रदेश	80.827	86.219
6.	महानदी	टिकरापारा	ओडिशा	50.489	51.404
7.	कावेरी	मुसिरी	तमिलनाडु	6.969	4.352
8.	ब्राह्मणी	जेनापुर	ओडिशा	16.304	16.493
9.	सुवर्णरेखा	घाटशिला	झारखंड	6.686	7.348
10.	नर्मदा	गरुड़ेश्वर	गुजरात	18.953	23.337
11.	बैतरणी	आनंदपुर	ओडिशा	4.352	10.470
12.	माही	खानपुर	गुजरात	4.541	5.456
13.	साबरमती	वौथा	गुजरात	2.649	2.144

नोट: जून से वर्ष को जल वर्ष के रूप में लिया गया है,

Water Sector-News

- राष्ट्रीय प्रोजेक्ट शाहपुर कंडी बांध का 85 प्रतिशत काम पूरा, 8 माह में बंद होगा पाक को जा रहा पानी (दैनिक भास्कर, 01.12.2022)
- जल जीवन मिशन — समिति के समक्ष पेश 27 में से छह डीपीआर मिलीं मानकों के अनुरूप (राष्ट्रीय सहारा, 06.12.2022)
- केन—बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को दी मंजूरी (अमर उजाला, 09.12.2022)
- दिल्ली के साथ पानी साझा करने की योजना से पीछे हटा उत्तर प्रदेश (अमर उजाला, 12.12.2022)
- केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के लिए साबित होगी वरदान : शेखावत (राष्ट्रीय सहारा, 14.12.2022)
- नमामि गंगे विश्व की 10 प्रमुख पहलों में शामिल (अमर उजाला, 15.12.2022)
- यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ा, कम प्रेशर से आएगा पानी (नवभारत टाईम्स, 18.12.2022)
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 224 परियोजनाएं पूरी (हिन्दुस्तान, 20.12.2022)
- महाराष्ट्र के मंत्री ने कर्नाटक को दी पानी रोकने की चेतावनी (अमर उजाला, 22.12.2022)
- गंगा की सफाई पर चार राज्यों में खर्च होंगे 27 सौ करोड़ रुपए (जनसत्ता, 28.12.2022)
- सीमा विवाद के बाद अब महाराष्ट्र ने अलमाटी बांध पर जताया एतराज (अमर उजाला, 30.12.2022)

Gallery

वैनगंगा डिवीजन, एमसीओ, सीडब्ल्यूसी, नागपुर के तहत वर्धा नदी पर जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन बामनी (जीडीएसक्यू) में सीडब्ल्यूसी की एक नवीनीकृत जल गुणवत्ता प्रयोगशाला (स्तर- I), नदी के पानी की गुणवत्ता पर 6 परीक्षण करती है: तापमान, रंग, गंध, पीएच , विद्युत चालकता और विघटित ऑक्सीजन।

मुख्य अभियंता, न.बे.स., अधीक्षण अभियंता (सम.), अधिशासी अभियंता (नर्मदा मंडल), के.ज.आ., भोपाल द्वारा मध्य नर्मदा उपमंडल-I, नर्मदापुरम के अधीनस्थ स्थल नर्मदापुरम, स्थल सांडिया , स्थल बरमान, स्थल बेल्खेडी एवं स्थल गाडरवारा पर डिस्चार्ज लिया गया एवं निरीक्षण किया गया

माही एवं तापी बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग गांधीनगर में दिनांक 23-12-2022 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन श्री द. सो. चासकर, मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में किया गया । कार्यशाला में, "व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन (वेतन पर आयकर, आयकर में बचत, भविष्य की वित्तीय योजना आदि)" एवं "संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के अनुभव" इन विषयों पर प्रस्तुतिकरण तथा विस्तृत चर्चा हुई।

भारत सरकार के माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में सीडब्ल्यूसी (मुख्यालय) का दौरा किया और अध्यक्ष, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सदस्य (डी एंड आर), सदस्य (आरएम) के साथ बातचीत की।), मुख्य अभियंता (एचआरएम) और अन्य अधिकारी 19.12.2022 को।

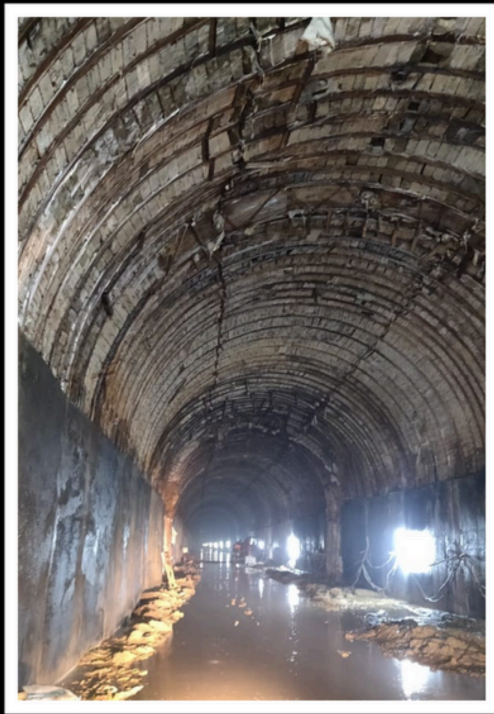

श्री हरीश उंबरजे, निदेशक और श्री करण रघुवंशी, उप निदेशक निगरानी निदेशालय, एमसीओ, सीडब्ल्यूसी नागपुर ने पीएमकेएसवाई-एआईबीपी (राष्ट्रीय परियोजनाएं) और सीएडीडब्ल्यूएम के तहत शामिल परियोजना घटकों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए गोसीखुर्द (राष्ट्रीय-वृहद) सिंचाई परियोजना के विभिन्न घटकों जैसे दाहिनी तट नहर, बाईं तट नहर, घोड़ाज़ारी शाखा नहर, मोखाबर्डी एलआईएस, अकोट एलआईएस, नेरला एलआईएस और उनकी कमान का 15.12.22 से 16.12.22 तक दौरा किया। ।

15.12.2022 को, अधिशाषी अभियंता, अपर कृष्णा डिवीजन ने आईटीपी @एनडब्ल्यूए पुणे में कार्यरत जूनियर इंजीनियरों के लिए आरटीके जीपीएस के प्रदर्शन की व्यवस्था की। श्रीमती सत्या, एसडीई, यूबीएसडी और जूनियर इंजीनियर ने कार्य प्रक्रिया के बारे में बताया।

इतिहास- सिंचाई और विद्युत के लिए चंबल कास्केड

चम्बल घाटी परियोजनाएँ (विशेषताएं एक नजर में)				
	गांधीसागर बांध	राणाप्रताप सागर बांध	जवाहर सागर बांध	कोटा बैराज
	I चरण	II चरण	III चरण	I चरण
स्थान:	मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चौरसीगढ़ किले से लगभग 8 किमी (5 मील) नीचे चंबल नदी पर एक बांध	चंबल नदी पर कोटा बैराज से लगभग 51.5 किमी (32 मील) ऊपर और गांधी सागर बांध से 56.33 किमी (35 मील) नीचे की ओर एक बांध।	राजस्थान में बूंदी जिले में कोटा शहर से 29 किमी (18 मील) ऊपर चंबल नदी पर एक बांध	राजस्थान में कोटा शहर से 0.8 किमी (0.5 मील) ऊपर चंबल नदी पर एक बैराज
प्रकार	चिनाई गुरुत्वाकर्षण बांध	चिनाई गुरुत्वाकर्षण बांध	कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध	नदी के हिस्से में मिट्टी का बांध और बाएं किनारे पर चिनाई वाला स्पिलवे
लंबाई	514 m (1 685 ft)	1143 मी. (3 750 ft)	335.98 मी. (1 102 ft)	551.83 मी. (1 810 ft)
ऊंचाई	63.7 मी. (209 ft)	53.96 मी. (177 ft)	44.81 मी. (147 ft)	39.02 मी. (128 ft)
भंडारण क्षमता				
सकल भंडारण	7746 मिलियन क्यू मी.	2900 मिलियन क्यू मी.	67.8 मिलियन क्यू मी.	98.7 मिलियन क्यू मी.
सजीव भंडारण	6920 मिलियन क्यू मी.	1567 मिलियन क्यू मी.	116.04 मिलियन क्यू मी.	--
संस्थापित क्षमता	23 मेगावाट की 4 यूनिट और 27 मेगावाट की एक यूनिट	43 मेगावाट की 4 इकाइयां	33 मेगावाट की 3 इकाइयां	--
नहर				
दाईं मुख्य नहर		--	--	376.6 किमी (234 मील)
बाईं मुख्य नहर एवं शाखाएँ		--	--	169.05 किमी (1`05 मील)
कुल लागत (लाख रूपये में)	2355	2784	1842	444
लाभ				
सिंचाई	4.45 लाख हे(11 लाख एकड़)	1.21 लाख हे(3 लाख एकड़)	--	दायीं और बायीं मुख्य नहरें 5.67 लाख हेक्टेयर (14 लाख एकड़) को पानी की आपूर्ति करती हैं
बिजली	80 मेगावाट60 प्रतिशत लोड कारक पर	90 MW 60 प्रतिशत लोड कारक पर	60 000 KW 60 प्रतिशत लोड कारक पर	

चंबल घाटी विकास परियोजनाओं को राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की समृद्धि के लिए तीन चरणों में पूरा करने की योजना बनाई थी जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए 0.57 मिलियन हेक्टेयर (1.4 मिलियन एकड़) भूमि सिंचाई के तहत लाकर और 230 मेगावाट की सस्ती पनबिजली का उत्पादन कर, भारी, मध्यम और लघु उद्योगों को विकसित करके लाखों लोगों को सक्षम बनाकर उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा कर रही हैं तथा घाटी के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ा रही है।

सिंचाई और बिजली दोनों उद्देश्यों के लिए चंबल नदी की विशाल क्षमता का उपयोग करने का विचार पहली बार 1943 में रखा गया था, लेकिन चंबल घाटी विकास के पहले चरण पर वास्तविक कार्य वर्ष 1953-54 से ही शुरू किया गया था।
चंबल घाटी विकास दो राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश (मूलरूप से मध्य भारत) का एक संयुक्त उद्यम था। इन राज्यों को डेढ़ दशक की अल्प अवधि में चंबल घाटी विकास योजनाओं की उपलब्धियों पर गर्व हो सकता है। यह केवल इन परियोजनाओं के लाभ और लागत को समान रूप से साझा करने के लिए शुरू से ही समझौतों पर जल्दी सहमत होने में अंतर-राज्य सहयोग के कारण ही संभव हो सका।

चम्बल नदी

चम्बल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली कुछ नदियों में से एक है और यह दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश के बड़े हिस्सों में बहती है और इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश में महोवा के पास विंध्य पर्वतमाला के उत्तरी ढलानों पर होती है और कोटा शहर के लगभग 96.6 किमी (60 मील) ऊपर चौरासीगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करने से पहले मध्य प्रदेश में 362.25 किमी (225 मील) तक बहती है। मध्य प्रदेश में बहते समय इसमें रेतम, सिवनी, छोटीकली सिंध, शिप्रा और गंभीर जैसी कई सहायक नदियाँ शामिल होती हैं। नदी पहले उपजाऊ मालवा पठार से बहती है और फिर चौरासीगढ़ में एक गहरे गार्ज में प्रवेश करती है। यह गार्ज कोटा शहर तक लगभग 96.6 किमी (60 मील) तक फैली हुई है। फिर यह नदी राजस्थान में 305.9 किमी (190 मील) तक बहती है, जहां कालीसिंध, पार्वती, मेज और बनास जैसी कुछ और सहायक नदियाँ इसमें मिलती हैं। इसके बाद नदी मैदानों और खड्डों से होकर बहती है और धौलपुर के पास उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है।चंबल की कुल लंबाई 965 किमी (600 मील) है।

नदी का तल अपने स्रोत और कोटा शहर के बीच 624.84 मीटर (2050 फीट) नीचे गिर जाता है जहां यह मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। इस गिरावट में से 121.92 मीटर (400 फीट) केवल गार्ज भाग में यानी चौरासीगढ़ और कोटा शहर के बीच लगभग 96 किमी (60 मील) की दूरी तक स्थित है।यह गार्ज एकमात्र पहुंच थी जहां चिनाई और कंक्रीट बांध स्थित हो सकते थे। बांधों को इस प्रकारबनाया जाना था कि 121.92 मीटर (400 फीट) से जल गिरावट का अधिकतम लाभ बिजली उत्पादन के लिए उठाया जा सके। कुछ वर्षों की जांच के बाद लागत और लाभों के समान बंटवारे के आधार पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में नदी के विकास की योजना बनाई गई थी।

चंबल घाटी विकास योजना को प्रतिबंधित वित्तीय संसाधनों के कारण दूसरा, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में तीन चरणों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया था।

चरण -1

इस चरण में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर एक चिनाई वाला गुरुत्व बांध, जिसे गांधी सागर बांध कहा जाता है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में बड़े क्षेत्रों की सिंचाई के लिए दाएं और बाएं किनारे की मुख्य नहरों के साथ कोटा शहर के पास एक बैराज शामिल है।

गांधी सागर 63.70 मीटर (209 फीट) ऊंचा चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है जिसकी सकल भंडारण क्षमता 7745.94 मिलियन घन मीटर (6.28 मिलियन एकड़ फीट) है। इस बांध पर बिजली उत्पादन के लिए 47.24 मीटर (155 फीट) का हेड उपलब्ध कराया गया है। गांधी सागर पावर स्टेशन में पांच जनरेटर स्थापित हैं, जिनमें से चार 23,000 किलोवाट और एक 27,000 किलोवाट क्षमता का है।

कोटा शहर के पास स्थित कोटा बैराज चंबल घाटी के इस झरने के विकास पैटर्न की आखिरी संरचना है। इसका मुख्य कार्य राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में 5.67 लाख हेक्टेयर (14 लाख एकड़) भूमि की सिंचाई के लिए नदी के दाएं और बाएं किनारे पर निर्मित नहरों के जल स्तर को बढ़ाना है।
दाहिनी मुख्य नहर 363.86 किमी (226 मील) लंबी है और राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के क्षेत्रों को जलआपूर्ति करती है। इसके शीर्ष पर 188.46 घन मीटर (6 656 घन फीट)/सेकंड की डिजाइन क्षमता है।

बायीं मुख्य नहर विशेष रूप से राजस्थान के क्षेत्रों को पानी देती है। लगभग 3.22 किमी (दो मील) चलने के बाद, यह लगभग 169.05 किमी (105 मील) की कुल लंबाई वाली दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। नहर को इसके शीर्ष पर 42.47 घन मीटर (1 500 घन फीट)/सेकंड के लिए डिज़ाइन किया गया है।

राजस्थान में 1.61 लाख हेक्टेयर (4 लाख एकड़) भूमि को पहले ही आर्द्र खेती के अंतर्गत लाया जा चुका है, जबकि मध्य प्रदेश में 1.01 लाख हेक्टेयर (2.5 लाख एकड़) भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया जा चुका है।

चरण II

इसमें चित्तौड़ जिले के रावतभाटा में 53.95 मीटर (177 फीट) ऊंचा चिनाई बांध शामिल है, जो गांधी सागर से लगभग 48.3 किमी (30 मील) नीचे की ओर और कोटा बैराज से 48.3 किमी (30 मील) ऊपर की ओर स्थित है। मेवाड़ राज्य पर शासन करने वाले इस राजपूत राजा की वीरता को श्रद्धांजलि के रूप में इस बांध का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया है।
इस जलाशय की उपयोग किए जाने योग्य भंडारण क्षमता 1566.46 मिलियन घन मीटर (1.27 मिलियन एकड़ फीट) है, जबकि सकल भंडारण 2 898.56 मिलियन घन मीटर (2.35 मिलियन एकड़ फीट) है।यह भंडारण चरण I के तहत निर्मित नहर प्रणाली के तहत 1.21 लाख हेक्टेयर (3 लाख एकड़) के लिए अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है, जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच कुल सिंचाई क्षमता 4.45 लाख हेक्टेयर (11 लाख एकड़) से बढ़कर 5.67 लाख हेक्टेयर (14 लाख एकड़) हो जाती है।

राणा प्रताप सागर पावर स्टेशन बांध के बिल्कुल निचले हिस्से में बाएं किनारे पर स्थित है। यहां 43000 किलोवाट की चार उत्पादन इकाइयां स्थापित हैं।

बांध, सुरंग और पावर हाउस सहित अधिकांश सिविल इंजीनियरिंग कार्य जून 1967 में पूरे हो गए थे और 1967 के मानसून में जलाशय में कुछ पानी जमा हो गया था।

बांध के सत्रह शिखर द्वार, 18.29 मीटर x 8.53 मीटर (60 फीट x28 फीट) भी स्थापित किए गए हैं और जलाशय को उसकी पूरी डिजाइन क्षमता तक भरा जा सकता है।
43 000 किलोवाट उत्पादन की चार इकाइयों में से पहली फरवरी 1968 में और दूसरी इकाई जुलाई 1968 में स्थापित की गई थी। तीसरी दिसम्बर 1968 में और चौथी इकाई मई 1969 में स्थापित की गई।

चरण-III

विकास के अंतिम चरण में 44.8 मीटर (147 फीट) ऊंचा कंक्रीट बांध, जवाहर सागर बांध, केवल बिजली उत्पादन के लिए कोटा बैराज से लगभग 25.76 किमी (16 मील) ऊपर की ओर बनाया जा रहा है। इस जलाशय में कोई महत्वपूर्ण भंडारण क्षमता नहीं है। इस स्टेशन पर 33,000 किलोवाट की तीन उत्पादन इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

परियोजना के जवाहर सागर बांध, पावर हाउस और टेल रेस टनल पर काम अब प्रगति पर है।

स्टेशन पर लगने वाले सभी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक उपकरण कनाडा से पहले ही मिल चुके हैं। पहली इकाई के 1971 में चालू होने की संभावना है और परियोजना का काम 1971-72 में पूरा होने की योजना है।

चंबल घाटी विकास के तीन चरणों की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि प्रत्येक चरण के पूरा होने के तुरंत बाद लाभ मिलना शुरू हो जाता है।

अंतरराज्यीय शेयर

इस बहुउद्देशीय परियोजना के सिंचाई और बिजली घटकों के बीच लागत का बंटवारा भी दोनों भाग लेने वाले राज्यों की हिस्सेदारी है।

लाभ

सिंचाई

परियोजना के तहत परिकल्पित क्षेत्र के पूर्ण विकास पर, राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य में लगभग 2.84 लाख हेक्टेयर (7 लाख एकड़) के लिए सिंचाई उपलब्ध होगी। राजस्थान सिंचाई के तहत 1,927.75 लाख रुपये के कुल व्यय के साथ, कृषि योग्य कमांड क्षेत्र में प्रति एकड़ सिंचाई की लागत लगभग 275 रुपये बैठती है। कुछ कारणों से यह लागत थोड़ी बढ़ने की संभावना है क्योंकि लगभग 0.40 लाख हेक्टेयर (एक लाख एकड़) क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई के विकास के लिए पूंजीगत व्यय किया जाएगा।

विद्युत

चरण I, II और III के तहत बिजली उत्पादन के लिए राजस्थान का कुल निवेश रु.2 689.75 लाख है।
तीनों बिजलीघरों की स्थापित क्षमता 390000 किलोवाट है, जिसमें राजस्थान 50 प्रतिशत तक भागीदार है। स्थापित क्षमता के आधार पर बिजली की लागत इसलिए प्रति किलोवाट 1378 रुपये बैठता है।
यह आकलन किया गया है कि 100 प्रतिशत लोड फैक्टर के अनुरूप 138,000 किलोवाट या 60 प्रतिशत लोड फैक्टर के अनुरूप 230,000 किलोवाट के आधार पर इन तीन स्टेशनों से वार्षिक उत्पादन लगभग 1209 मिलियन किलोवाट होगा ।
इस प्रकार चंबल घाटी विकास के तहत परियोजनाएं भाग लेने वाले राज्यों को उचित कम लागत पर सिंचाई और बिजली दोनों लाभ प्रदान कर रही हैं।

(स्रोत: भगीरथ अक्टूबर 1970)

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- डॉ. बी.आर.के. पिल्लै, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री भूपिंद्र सिंह, निदेशक(टीसी) – सदस्य
- श्री सुनीलकुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी–सी)- सदस्य
- श्री अनंत कुमार गुप्ता, निदेशक (ज.प्र.अभि.) – सदस्य
- श्री अर्जेश कुमार मधोक, उप निदेशक (ज.प्र.अभि.) – सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) – सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव
- हिन्दी अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in